

संपादकीय बजट से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का परिदृश्य

एनडीए-इण्डिया गठबंधन दोनों को मिली चेतावनी

यह दुर्भाग्य है कि सन् 2024 के लोकसभा चुनाव में दो प्रमुख पक्ष इण्डिया गठबंधन और एन.डी.ए. मतदाताओं का मन्तव्य नहीं समझ रहे हैं। जनता ने भाजपा को नकारा नहीं है, उन्हें बहुमत के करीब पहुंचाकर उन्हें फिर से सरकार बनाने का च्योता दिया है। परन्तु जनता ने बिखरे हुए इण्डिया गठबंधन को भी ताकत दी है। पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाकाआउट किया, यह कहकर कि जब वे बोल रही थीं तो उनका माइक बंद कर दिया गया। अब इसके उत्तर में तुरंत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता जी को उनके अनुरोध पर लंच से बोलने का मौका दिया गया और सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का समय निर्धारित था। अब ममता स्वयं एक पार्टिसिपेंट थीं वित्त मंत्री की हैसियत से। वे आयोग की अधिकारी नहीं हैं। आयोग को ही स्पष्टीकरण देना चाहिए। असल में मोदी जी के आने के बाद योजना आयोग (प्लैनिंग कमीशन) को भंग कर दिया गया। भाजपा सुधार बोस का गुणागान करती है। स्वयं बोस ने कहा था कि आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन बनना चाहिए जिसके अध्यक्ष नेहरू होंगे। अब नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ड्रान्सफॉर्मिंग इण्डिया। अब इसमें आयोग शब्द कहाँ से आ गया। और आयोग से सरकार को इतना ही प्यार था तो योजना आयोग को भंग ही क्यों किया गया। आज आप सरकार की नीति पर कोई टिप्पणी करें तो आप देशद्रोही हैं। हमारे शास्त्रोंमें नेति, नीति का उल्लेख है अर्थात् हम नकारते हुए सत्य तक पहुंचते हैं। योजना आयोग और नीति का उद्देश्य देश में संतुलित विकास है ताकि सभी राज्य तरकीब कर सकें। अब बजट में जो पिटारा विहार और आंध्र प्रदेश के लिए खोला गया है, वह तो स्पष्ट रूप से एन.डी.ए. को साधना ही है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि सरकार की स्थिरता देश के लिए परम्परा आवश्यक है। असल में भाजपा अपने शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से तो मंत्रिणा होती ही रहती है। असल में भाजपा राज्यों में अधोसंरचना का विकास केन्द्र की सहमति से ही तय होता है। अतः अच्छा हो कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं और उनसे प्रधानमंत्री की मंत्रिणा होती उहें बोलने का अधिक समय दिया जाये। वैसे भी विपक्ष की ओर से केवल ममता बनर्जी ही नीति आयोग की बैठक में उपस्थित थीं। पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, कर्ल, तमिलनाडु, झारखण्ड, मिजोरम के मुख्यमंत्री आए ही नहीं। तो ममता बनर्जी को नियम का हवाला देकर उन्हें पूरा बोलने न देना, नीति (आयोग) के उद्देश्य के विपरीत है।

विशेष लेख

नए एक्सटेंशन वाली दिशा में आगे बढ़ते मोहन यादव

प्रकाश भटनागर

किसी अच्छे काम को आगे ले जान समझदारी है। वैसे भी मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री भले ही बदले हों लेकिन सरकार में वहीं राजनीतिक दल है। इसलिए ऐसे में किसी भी सकी प्रदेश में जड़े बहुत गहरी जम चुकी हैं। इसलिए ऐसे में किसी भी समझदारी में चार चांद लगाने जैसा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने हाल ही में इस तरह की नीति और नीयत, दोनों का बार फिर ठोस तरीके से परिचय दिया है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना लाभ पा रही 46 लाख लाडली बहनों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी रखी जा रही है। इस साल अगस्त में तो सभी लाडली बहनों को बीमी के उपहार के तौर पर ढाई सौ रुपए के शपुन का लाभ भी बरकरार दिया गया है। इस बात में कोई संशय नहीं कि डा. यादव के पूर्ववर्ती वराज सिंह चौहान ने अपने समय में % महिला कल्याण से संभावनाओं की निर्माण' वाला अद्भुत कफामूल लागू कर जबरदस्त तरीके से भाजपा को यासी लाभ दिलाया था। चौहान ने लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना योजना तक के सफर में अनेक ऐसे पड़ाव स्थापित किए, जिनसे जयपा को तगड़ा राजनीतिक माइलेज मिला। यही वजह रही कि जब य में डा. मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, तब मुख्य विपक्ष कांग्रेस ने बदल कर पर यह कहकर ताबड़ोड़ प्रहर किए कि लाडली बहना योजना ब बंद की जा रही है। जाहिर है कि कांग्रेस भी इस बात को भांप चुकी है।

कि यदि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को कमज़ोर करना है, उसके महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों और लगभग भाजपा का बोट बैंक। चुनीकी महिलाओं के लाभ की योजनाओं को ही टारगेट करना होगा। दल ने विधानसभा चुनाव से पहले भी महिलाओं को सम्मान निधि और सर्ते सिलेंडर देने की बात कहकर शिवराज की योजनाओं को उंटर करने का प्रयास किया था। कांग्रेस दोनों ही अवसरों पर असफल रही। खासतौर से लोकसभा चुनाव में ऐसा होने की प्रमुख वजह यह कि मोहन यादव ने इस दिशा में टस से मस हुए बगैर जस की तस धरनी चढ़रिया' से भी एक कदम आगे जाकर शिवराज के कार्यक्रमों को छेत्र और प्रगति प्रदान की। लाडली बहना योजना तो बदस्तर जारी है, डा. हन यादव ने शुरू में बताए गए और भी महिला-हितेषी निर्णयों के अध्यम से इस दिशा में नए काम शुरू कर दिए हैं। यह एक तरह से वह स्टेंशन भी है, जो किसी चले आ रहे' को चलते ही जाना है' वाला चाचर भी प्रदान करता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब एक बात लागू करती है कि वह गर्भवती महिलाओं को मुफ्त नोग्राफी जांच की सुविधा देगी, तो यह शिवराज की जननी सुरक्षा जना का एक ठोस तथा निर्णायक एक्स्टेंशन ही कहा जाएगा। मामला श्वेत ही सियासी मुनाफे बाला है। वर्ष 2003 में उमा भारती ने प्रदेश के बीतर तक जाकर राजनीतिक मुद्दों को हवा दी। घरों में बिजली कमी और सड़कों पर गड़ों के ऐसे विषय प्रमुखता से उठाए, जो सीधे वरार से जुड़ी समस्याओं को छोड़ते हैं। दिग्विजय सिंह चुनावी मैनेजमेंट थोरी में मगन रहे और उमा ने अपने ऐसे मुद्दों के जरिए कहानी घर-की' वाली शैली में प्रदेश की जनता के दर्द को सीधे भुना लिया। फिर वराज। उन्होंने घर में भी महिलाओं की शक्ति पर खास फोकस किया। जो जासानी है। अब डा. मोहन यादव भी इस दिशा में न सिर्फ आगे चुके हैं, बल्कि वे नवाचार भी अपना रहे हैं। अब भले ही इसके जरिए महिला वोटरों को भाजपा से जोड़े रखने की रणनीति पर अमल किया जा सकता हो, लेकिन तुष्टिकरण और जात-पात की राजनीति से बहुत अलग यह माला औरों के मुकाबले %अधिक साफ-सुथरा' कहा ही जा सकता। खास बात यह भी कि डा. यादव के आधी आबादी से जुड़े ऐसे फैसले न पूरे विश्वास को भी आकर देते दिखते हैं। वह यह कि इन कदमों से इन सन्देश और संकेत भी जाता है कि सरकार लाडली बहना योजना की विश्वास को तीन हजार रुपए प्रतिमाह करने की दिशा में भी आगे बढ़ सकती है। अखिर मामला स्त्री शक्ति को और शक्ति देकर खुद के लिए सियासी शक्ति के संचय में वृद्धि करने की कोशिश का जो ठहरा। शिवराज से कर डा. मोहन यादव तक को देखते हुए इस दिशा में एक और बात ही जा सकती है। वह यह कि अखिरकार काम बोलता है।

ડા. જયંતાલાલ ભંડારા

ओर मक इन इंडिया पहलों के तहत दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पिछले वर्ष के 9509 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल आवंटन 21085 करोड़ रुपए किया गया है। बहुप्रचारित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के अभूतपूर्व बजट प्रावधान हैं। खिलौना, जूते, चमड़े, उद्योगों के विकास के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्ट्रिक्ट के विकास का संशोधित कार्यक्रम भी प्रोत्साहित किया गया है। इसके तहत कंपनियों को देश में सिलिकॉन और कंपांडिंड फैब्रिकेशन (फैब), डिस्ट्रिक्ट के असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग व पैकेजिंग (एटीएमपी), आटडसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली और टेस्ट व डिजाइन करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2024-25 के बजट से भारत से निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पिछले वर्ष 2023 में जी-20 के सफल आयोजन के साथ दुनिया में यह बात उभरकर सामने आई है कि 'चीन प्लस वन' रणनीति के तहत भारत दुनिया के सक्षम व भरोसेमंद देश के रूप में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वाले देश के रूप में नई भूमिका निभा सकता है। दुनिया का कोई दूसरा देश इस तरह के परिचालन के पैमाने और आकार की पेशकश नहीं कर सकता, जैसा भारत में उपलब्ध है। इसके अलावा जी-20 में घोषित हुए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कारिंडोर (आईएमईसी) के माध्यम से रेल एवं जल मार्ग से भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसरों का ऐसा ढेर लगाया जा सकेगा, जिससे चीन की तुलना में भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता भी बढ़ जाएगी। नए बजट के प्रावधानों से ऐसे में जहां भारत एक ओर अधिक रणनीतिक प्रयासों से भारतीय बाजार में चीन के प्रभुत्व को कम कर सकता है, वहाँ दूसरी ओर दुनिया के बाजार में उद्योग-कारोबार, निर्यात और निवेश के अधिक मौकों को मुश्किलों में ले सकता है। हम उमीद करें कि वर्ष 2024-25 के नए बजट के तहत वित्तमंत्री सीतारमण ने मैन्युफेक्चरिंग और निर्यात बढ़ाने के लिए 100 शहरों में प्लग एंड एल्युविडा वाले औद्योगिक पार्क और एमएसएमई को आयात घटाने व निर्यात बढ़ाने और मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए मजबूती के जो विकास कवच दिए हैं।

अडानीपरस्ती-इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो माई-बाप

संजय परात

सरकार अब माइ-बाप है। वह कानून बनाता है ताकि आम जनता इसके दायरे में रहे। लेकिन इस कानून को मानना या न मानना, उसकी मर्जी? इस कानूनों में भी इतने चोर दरवाजे जरूर रखे जाते हैं कि समाज का वह प्रभुत्वशाली वर्ग इसका आसानी उल्लंघन कर सके, जिसके सहारे ये सरकार टिकी होती है। कॉर्पेरेट अडानी और मोदी सायर की सरकार बीच यही रिश्ता है, जो हस्तेव के मामले में साफ साफ दिखता है। हस्तेव के स्थानीय आदिवास समुदायों के जबरदस्त विरोध और इस विरोध व कमज़ोर करने के लिए प्रशासन द्वारा खनन प्रभावित गांवों की जबरदस्त धेराबंदी के बीच हस्तेव अरण वन क्षेत्र में स्थित तीसरे कोयला ब्लॉक के एक्सटेंशन में उत्खनन शुरू करने के लिए आज ज सुनवाई हो रही है। यह जन सुनवाई भी उस गांव हो रही है, जो खनन प्रभावित नहीं है और उपर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के आधार पर की रही है, जो वर्ष 2019 की है और पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के अनुसार ही, जिसकी कोई वैधता नहीं है। लेकिन अडानी की सेवा में मोदी-सायर राज कोई नियम-कायदे आड़े नहीं आते। उल्लेखनीय है कि हस्तेव अरण के जंगलों को मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, जिसकी देश-दुनिया में जलवायु और पर्यावरण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है। कॉर्पेरेट लू के लिए आज ये जंगल अडानी के निशाने पर हैं और मोदी-सायर राज की पूरी ताकत अडानी के साथ खड़ी है।

का वास्तविक अनुमान / लाख ह, लाकर सरकार केवल 2,73,757 (39.11 ल) पेड़ों की कटाई की ही घोषणा कर रही है। स्पष्ट है कि वास्तविक वन विनाश को छुपाने के लिए ही पेड़ों की कटाई के फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। इस वन विनाश की भरपाई के लिए वृक्षारोपण के नाम पर दिए जा रहे आंकड़े भी इतने ही फर्जी हैं। वैज्ञानिक तरीके से एक एकड़ में अधिकतम 2000 पौधों का रोपण हो सकता है। पीईकबी खदान के लिए पेड़ों की कटाई से हुए नुकसान के लिए जिन 53.40 लाख से अधिक पौधों को लगाने का दावा किया जा रहा है, उसके लिए न्यूनतम 2670 एकड़ (लगभग 1,168 हेक्टेयर) भूमि की जरूरत होगी। ये पेड़ कहां लगे हैं, खनन प्रभावित लोगों को नहीं मालूम। मोदी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं, ताकि कोई स्वतंत्र एजेंसी सरकार के इस दावे की जांच पड़ताल कर सके! पौधारोपण के इसी अनुपात का पालन किया जाए, तो केते एक्सटेंशन के लिए पेड़ों की कटाई से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए इस सरकार को 1.55 करोड़ पौधे लगाने होंगे। इसके लिए कम से कम 7750 एकड़ भूमि (लगभग 3100 हेक्टेयर) की जरूरत पड़ेगी। यह भूमि कहां से आयेगी, इस पर भी सरकार मौन है। कथित वृक्षारोपण का पूरा मामला एक बड़ा गड़बड़ाला है। वैसे इस सरकार को इतना भी ज्ञान नहीं है कि पेड़ नहीं, बल्कि पौधों का रोपण होता है, जो सही देखभाल के साथ दसियों साल बाद युवा होकर फल-फूल देने वाले पेड़ बनते हैं। वन क्षेत्र प्राकृतिक होते हैं और इसके आधार पर बनने वाली

जव-वावधाता आर पयावरण, पारास्थातिका तत्र का निर्माण करती है। कथित वृक्षारोपण, जो दरअसल पौधा रोपण होता है, इस प्रकृति का और पेड़ों की कटाई से होने वाली पारिस्थितिकी के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। हसदेव के जंगलों के विनाश के बदले किया जाने वाला कोई भी मानव निर्मित जंगल देश-दुनिया की पारिस्थितिकी को बनाने वाले फेफड़े का निर्माण नहीं कर सकता। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक से निकलने वाला कोयला राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के अनुसार, उसे अपने कोयला आधारित पावर प्लाटों को चलाने के लिए हर साल लगभग 200 लाख टन कोयले की जरूरत है। लेकिन इससे केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में उत्खनन का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी जरूरत वर्तमान में चल रहे दो कोयला खदानों से पूरी हो जाती है। फिर, राजस्थान सरकार जिस गति से सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ा रही है, 6 साल बाद कोयला आधारित बिजली पर उसकी निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाने वाली है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जवाब अडानी परस्ती का एक नमूना है। केते एक्सटेंशन का कोयला राजस्थान सरकार की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि आदमी की तिजोरी के लिए जरूरी है, जिसने पिछले दस सालों में वर्तमान में चालू दो खदानों से ही 28000 करोड़ रुपयों की कोयला चोरी की है।

(टिप्पणीकार आखल भारताय किसान सभा संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।

پاکستان میں ہندوؤں پر ایش نیندا کانون کا خطرناک

विनाय

پاکیسٹان بُرُو اف س्टَر्टِسٹِک (پیبی ایس) پیشلے دینोں آنکڈے جاتی کر بتاتا کہ پاکیسٹان میں ہندوؤں کی آبادی بढگا گردی ہے۔ اس سلامیک ریپورٹ پاکیسٹان میں 2017 میں ہندوؤں کی آبادی 3 لाख تھی جو 2023 میں بढکر 38 لाख تک پہنچا گردی۔ سامراجنا ہوگا کہ پاکیسٹان کے ہندو باغھل کے رہنگانی ایلکاؤن میں کبھی سالنیک سے جنگاننا ہوتا ہے۔ نہیں، فیر وہاں سیخوں کو الگ سے گینا جاتا ہے۔ سرکار کی آنکڈے کو اب پاکیسٹان نیوارچیت ہندو نہتی ہی فوجی بات رہے ہے۔ سامراجنا ہوگا کہ اک تو پاکیسٹان میں ہندو لڈکیوں کے جبارن اپرہن اور دھرم پریورٹن پر کبھی کوئی کارکردگی ہوتی نہیں، دوسرا وہاں سرکار بھی نہ چاہتی کہ اعلپسِ سُنْحُکوں کی واسطیک سُنْحُک دیکھائی جائے۔ یہ مرکوٹ کے آسپاس سکنڈا بھر گا ہندو باغھلی ہے، اور وہاں سدک، پانی، سکول جسے سُعیداً ہے۔ پاکیسٹان کے بडے سانگठن پاکیسٹان ہندو کا ڈیمیشنل کے چیری میئن ڈا۔ رسمے کوئامار وانکوانی اور مُوتھا دی راشیہ مُوہمنٹ کے پ्रتی� اس سُنْحُک سدستھ ڈا۔ مانگلا شارما این آنکڈے کو جھوٹ باتاتے ہوئے دسٹاویج پرسُت کر رہے ہیں۔ سرکاری ریکارڈ میں 2017 میں ہندوؤں کی آبادی 44 لाख 44 ہجڑا 870 گینی گردی ہے۔ اس سلیتیت آج آبادی اک کاروڈ سے اधیک ہے۔ اعلپسِ سُنْحُکوں پر ہونے والے اُتھاچار اور بے دبای پر پردہ ڈالنے کے لیے اس ترہ کے فوجی آنکڈے پے شکنے کیے جا رہے ہیں۔ پیبیسی کے آنکڈے تو اسے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آبادی میں سات لाख کی بढگتی بات کے عکسی سُنْحُک 33 لाख پہنچنے کا داوا کر رہے ہیں۔ وہاں پارسی مہاج 2348 رہ گئے لیکن سیخوں کے

संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। पाकिस्तान में 1951 में 1.60 फीसद हिन्दू आबादी थी। 1961 में 1.45 फीसद, 72 में 1.11, 1981 में 1.85 और 2017 में 1.73 फीसद हिन्दू आबादी थी। इस साल यह आंकड़ा घट कर 1.61 फीसद रह गया है। चूंकि बड़ी संख्या में हिंदुओं के पास राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईसी) है ही नहीं, सो उनकी गणना होती नहीं वरना यह आंकड़ा एक करोड़ से अधिक होगा। देश में सबसे ज्यादा हिन्दू सिंध में, कुल आबादी का 8.73 फीसद हैं। पंजाब राज्य में 0.19, खैबर पख्तुन्बा में 0.02, बलोचिस्तान में 0.40 और इस्लामाबाद में 0.04 फीसद हिन्दू आबादी का सरकारी आंकड़ा है। राजस्थान से सटे थारपारकर जिले में सात लाख 14 हजार 698 हिन्दू रहते हैं, तो मीरपुरखास में पांच लाख के करीब, सघर में चार लाख 46 हजार हैं तो बदिन, हैदराबाद, टंडो मुहम्मदखान और रहीम यार खान जिलों में एक से डेढ़ लाख हिन्दू रहते हैं। यहां उमरकोट जिले की आबादी का 52.15 फीसद हिन्दू हैं और यहां के राजपूत शासक बड़े ताकतवर हैं। हिन्दू बाहुल्य इलाकों से भी कभी हिन्दू सांसद या विधायक चुने नहीं जाते क्योंकि इसकी आबादी के नाम ही वोटर लिस्ट में होते नहीं या उनके वोट और कोई डालता है। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनते हैं तेकिन कट्टरपंथी जमात के विरोध के चलते ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। दो साल पहले वहां 18 साल से कम के लोगों के धर्म परिवर्तन पर पाबंदी का कानून आया लेकिन मुस्लिम-मौलियियों के विरोध के चलते वापस ले लिया गया। वहां धर्म परिवर्तन को बाब अर्थात् पुण्य का काम कहा जाता है और इस्लामिक कानून के तहत ऐसी पाबंदी धर्म विरोधी कह कर गवर्नर ने कानून रद्द कर दिया था। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की बीते



साल की रिपोर्ट बेशर्म से स्वीकार करती है कि देश में हर साल अल्पसंख्यक समुदाय की कोई एक हजार लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और ये 12 से 25 साल उम्र की होती हैं। 2004 से 2018 के बीच अकेले सिंध प्रांत में 7430 हिन्दू लड़कियों के अपरहण के मामले दर्ज किए गए, कहने की जरूरत नहीं कि वहाँ बड़ी संख्या में मामले थाना पुलिस तक जाते ही नहीं हैं। चूंकि सिंध के बड़े जागीरदारों के यहाँ अधिकांश हिन्दू मजदुर हैं, और वह भी तीन-तीन पीढ़ियों से लगभग बंधुआ मजदुर की तरह, सो उनकी कोई आवाज नहीं होती। कराची शहर में हिन्दू आबादी डॉक्टर जैसे पेशे में सर्वाधिक है, तो सब्जी बेचने वाले भी अधिकांश हिन्दू हैं। पाकिस्तान का शिक्षा तंत्र सबसे जहरीला है, स्कूली किताबों में हिन्दुओं को खलनायक बताया जाता है और आजादी की लडाई में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की भूमिका को हिन्दू-मुस्लिम टकराव, वहाँ की किताबों में देश के हिन्दुओं की वफादारी को भारत के साथ जोड़ा जाता है, वहाँ किसी भी किताब में

किसा हन्दू चारत्र का ताराफ का हा नहा जाता। पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 20-22 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख था लेकिन जुलाई, 1977 में जिया उल हक ने देश में माशर्ल लॉ घोषित किया और संविधान में बदलाव कर गैर-मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता पर कई पार्बंदियां लगा दीं, पाकिस्तान में राष्ट्रपति मुस्लिम ही बन सकता है और सभी उच्च पदों पर मुस्लिम आयतों के साथ शपथ लेना अनिवार्य है। इसके कारण वहां हिन्दुओं को सदैव दोयम माना जाता है। पाकिस्तान में हिन्दुओं पर सबसे बड़ा खतरा वहां का ईश निंदा कानून है जिसकी आड़ में भीड़ हिंसा में किसी को भी मार देने पर कोई खास कार्यवाही नहीं होती। हिन्दू या सनातन धर्म का कम से कम तीन हजार साल पुराना अतीत सरहद पार है—मोईन जोद्रो या हड्डपा के रूप में और हिंगलाज और कटासराज मंदिर सहित कई प्राचीन इमारतों के रूप में, दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान बनते समय मुहम्मद अली जिन्ना ने वहां धार्मिक आबादी की बात की थी लेकिन अब पाकिस्तान %जिन्ना के पाकिस्तान से जेहाद के पाकिस्तान' में तब्दील हो गया है और इसका सबसे बड़ा खमियाजा हिन्दू आबादी को उठा पड़ रहा है। जनगणना के त्रुटिपूर्ण आंकड़े एक तरफ धर्मांतरण के पाप को ढंकने के काम आते हैं, तो दूसरी तरफ जिस आबादी का रिकार्ड नहीं उसके लिए मूलभूत सुविधाओं की चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती। भारत में नागरिकता कानून आने के बाद वहां से पलायन तेजी से हुआ है और शायद वहां की सरकार चाहती भी यही है लेकिन यह अनिवार्य है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान में हिन्दू धर्म और उससे जुड़े चिह्नों को सहेजने, हिन्दू आबादी को शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाए।

व्यापार समाचार

जुलाई में 3.20 लाख गाड़ियों की हुई बिक्री, नयी पेशकश और डिस्काउंट ऑफर्स से सेल्स में इजाफा

नईदिल्ली(एजेंसी)। नए मॉडल की पेशकश और बड़ी हुई छूट से भारत में यात्री बाहनों की रिटेल बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ी। उद्योग निकाय फाडा ने सोमवार को यह जानकारी दी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार जुलाई में कुल यात्री बाहन खुदरा बिक्री बढ़कर 3,20,129 इकाई हो गई, जबकि जुलाई 2023 में यह 2,90,564 इकाई थी। फाडा के उपाध्यक्ष सी.एस. विनेश बर्न ने कहा, डीलरों ने बताया कि उन्हें अच्छे उत्पाद व्यापक होने, आकर्षक योजनाओं और उत्पादों के व्यापक श्रृंखला से लाभ प्रिला है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश, उपमोक्ता भावना में कमी और तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण चुनौतियां उत्पन्न हुई, लेकिन अधिक प्रचार तथा बड़ी छूट के जरिये बिक्री को बनाए रखने में कामयाबी हासिल हुई। जुलाई में दोपहिया बाहनों की खुदरा बिक्री 17 प्रतिशत बढ़कर 14,43,463 इकाई ही, जो जुलाई 2023 में 12,31,930 इकाई थी। विनेश ने बताया कि संपर्क ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सकारात्मक मानसून प्रभाव तथा ग्रामीण आय बढ़ाने वाले सरकारी सहायता कार्यक्रमों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बाहनों की खुदरा बिक्री पिछले महीने सालाना आधार पर सात प्रतिशत बढ़कर 80,050 इकाई हो गई। हालांकि, जुलाई में डैनरेशन की बिक्री सालाना आधार पर 12 प्रतिशत घटकर 79,970 इकाई रह गई। फाडा ने जुलाई महीने की रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाहन पंजीकरण आंकड़े देश भर के 1,645 आरटीओ में से 1,568 से एकत्र किए।

सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल

नईदिल्ली(एजेंसी)। भारतीय शेयर बाजार में भले ही आज (सोमवार) को भारी गिरावट देखने को मिल रही ही, लेकिन सर्वांगीन बाजार में उठी गंगा बह रही है। रद्दअसल, शेयर बाजार के इतन सर्वांगीन बाजार में सप्ताह के पहले ही दिन उछाल बना हुआ है। इससे पहले बाजार हो निशान के साथ ओपन हुआ और सोना 70 हजार के पर चला गया, हालांकि इसमें 11 बजे के बाद थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। वहाँ शुरूआती बाजार में चांदी के दाम भी 83 हजार के ऊपर चले गए, इसके बाद चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। सुबह 11.30 बजे सोने का भाव 210 रुपये चढ़कर 22 कैरेट सोने का भाव 64,222 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। जबकि 24 कैरेट गोल्ड का भाव 70,060 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया, वहाँ चांदी का भाव इस समय 60 रुपये गिरकर 82,750 रुपये प्रति किग्रा पर आ गया। सुबह साथे ग्राह बजे मर्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.30 प्रतिशत यानी 212 रुपये गिरकर 70,001 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा है। जबकि चांदी का भाव 0.01 फीसदी यानी 7 रुपये गिरकर 82,486 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहाँ विदेशी बाजार यानी यूएस कॉमेंस्स पर सोने-चांदी का भाव बढ़कर के साथ कारोबार कर रहा है। फिलहार यूएस कॉमेंस्स पर सोना 0.36 प्रतिशत यानी 80.90 डॉलर चढ़कर 42,870.70 डॉलर प्रति ऑस पर कारोबार कर रहा है। जबकि चांदी के दाम 0.06 फीसदी यानी 0.02 डॉलर चढ़कर 28.41 डॉलर प्रति ऑस पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में सोना (22 कैरेट) 63,901 तो 24 कैरेट गोल्ड का भाव 69,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जबकि चांदी की कीमत यहाँ 82,240 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रही है। मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव 63,983 रुपये प्रति दस ग्राम तो 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 69,800 रुपये प्रति 10 ग्राम ही गई है। वहाँ चांदी का भाव मायानगरी में 82,430 रुपये प्रति किग्रा चल रहा है।

भारत के सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर में जुलाई में मामूली गिरावट

नईदिल्ली(एजेंसी)। भारत के सर्विस सेक्टर की वृद्धि जून की तुलना में जुलाई में थोड़ी धीमी रही। एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। योसीपी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया भारत सेवा पीएमसी कारोबारी गतिविधि सूचकांक जुलाई में 60.3 रही जबकि जून में 60.5 थी। खरीद व्यापक बूक्सांक की भावों में 50 से ऊपर अंक का मात्रलव गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। एचएसबीसी के मुख्य अर्थव्यवस्था (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा, जुलाई में सेवे क्षेत्र की गतिविधि थोड़ी धीमी गति से बढ़ी, नए कारोबार में और वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से घरेलू मांग से प्रेरित रही है। सेवा कंपनियां आने वाले वर्ष के लिए आशावादी हैं। सितंबर 2014 में इस सर्वेक्षण को शुरूआत के बाद से नए नियर्थ टेकों में तीसरी सेवों तेज वृद्धि हुई है, जिसका कारण दुनिया भर से भारतीय सेवाओं की मांग में वृद्धि है।

इंडसइंड बैंक ने एचएनआई/यूएचआई सेगमेंट के लिए पेश किया विशेष जरूरतों को पूरा करने वाला वित्तीय समाधान कार्यक्रम 'पायनियर प्राइवेट'

मुंबई: इंडसइंड बैंक ने अपने एक विशेष कार्यक्रम, 'पायनियर प्राइवेट प्रोग्राम' के लॉन्च की घोषणा की जिसके तहत हाई नेटवर्क इंडिविजुल एचएनडब्ल्यूआई की अनुपरूप व्यापक तात्त्विक समाधान प्रदान किये जाएंगे। एचएनआई की सेवा में यह व्यापक व्यूखला, पारपरिक से लेकर तात्त्वातीन, एस्टेट और एचएनडब्ल्यूआई ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप शानदार जीवनशैली का अनुभव प्रदान करता है, जिसका शोध-स्तरीय ग्राहकों को एक अपर्याप्त लाऊंडर, पिक-अप एवं ड्रॉप, मीटिंग एंड ग्रीट सेवा, वैश्वक गोल्फ प्रिविलेज, एकीकृत शोध ब्रांड और बहुत कुछ शामिल है। इसके लिए विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप समाधान प्रदान करने के प्रति इंडसइंड बैंक की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है। पायनियर प्राइवेट, एचएनआई/यूएचआई समुदाय की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप समाधान प्रदान करने के प्रति इंडसइंड बैंक की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है। पायनियर प्राइवेट को जूलाई अहेड़ की वाहनों में इतिहास बनाने' (हिन्दी लाइज़ अहेड़) की भावना के आधार पर तैयार किया गया है और यह समझदार यूएचएनडब्ल्यूआई की वित्तीय समाधानों का एक विशेष सेगमेंट है। इस खास कार्यक्रम को 'भवित्व में इतिहास बनाने' (हिन्दी लाइज़ अहेड़) की भावना के आधार पर तैयार किया गया है और यह समझदार यूएचएनडब्ल्यूआई की वित्तीय यात्रा की हर ज़रूरत को पूरा करता है।

परिष्कृत निवेश के अवसरों पर पर ध्यान केंद्रित करने वाले हर व्यक्तिगत समाधानों की तरफ, उच्चवृत्ति के प्रति हाप्तों को प्रदान की जाने वाली व्यूखला, पारपरिक से लेकर तात्त्वातीन, एस्टेट और एचएनडब्ल्यूआई ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप शानदार जीवनशैली का अनुभव प्रदान करता है। ये अभूतपूर्व लाभों और सुरक्षाओं के साथ आते हैं, जिसमें विशेष यात्रा लाभ-एयरपोर्ट लाऊंडर, पिक-अप एवं ड्रॉप, मीटिंग एंड ग्रीट सेवा, वैश्वक गोल्फ प्रिविलेज, एड ग्रीट सेवा, वैश्वक गोल्फ प्रिविलेज, एकीकृत शोध ब्रांड और बहुत कुछ शामिल हैं।

परिष्कृत निवेश के अवसरों पर पर ध्यान केंद्रित करने वाले हर व्यक्तिगत समाधानों की तरफ, उच्चवृत्ति के प्रति हाप्तों को प्रदान की जाने वाली व्यूखला, पारपरिक से लेकर तात्त्वातीन, एस्टेट और एचएनडब्ल्यूआई ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप शानदार जीवनशैली का अनुभव प्रदान करता है। ये अभूतपूर्व लाभों और सुरक्षाओं के साथ आते हैं, जिसमें विशेष यात्रा लाभ-एयरपोर्ट लाऊंडर, पिक-अप एवं ड्रॉप, मीटिंग एंड ग्रीट सेवा, वैश्वक गोल्फ प्रिविलेज, एड ग्रीट सेवा, वैश्वक गोल्फ प्रिविलेज, एकीकृत शोध ब्रांड और बहुत कुछ शामिल हैं।

परिष्कृत निवेश के अवसरों पर पर ध्यान केंद्रित करने वाले हर व्यक्तिगत समाधानों की तरफ, उच्चवृत्ति के प्रति हाप्तों को प्रदान की जाने वाली व्यूखला, पारपरिक से लेकर तात्त्वातीन, एस्टेट और एचएनडब्ल्यूआई ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप शानदार जीवनशैली का अनुभव प्रदान करता है। ये अभूतपूर्व लाभों और सुरक्षाओं के साथ आते हैं, जिसमें विशेष यात्रा लाभ-एयरपोर्ट लाऊंडर, पिक-अप एवं ड्रॉप, मीटिंग एंड ग्रीट सेवा, वैश्वक गोल्फ प्रिविलेज, एड ग्रीट सेवा, वैश्वक गोल्फ प्रिविलेज, एकीकृत शोध ब्रांड और बहुत कुछ शामिल हैं।

परिष्कृत निवेश के अवसरों पर पर ध्यान केंद्रित करने वाले हर व्यक्तिगत समाधानों की तरफ, उच्चवृत्ति के प्रति हाप्तों को प्रदान की जाने वाली व्यूखला, पारपरिक से लेकर तात्त्वातीन, एस्टेट और एचएनडब्ल्यूआई ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप शानदार जीवनशैली का अनुभव प्रदान करता है। ये अभूतपूर्व लाभों और सुरक्षाओं के साथ आते हैं, जिसमें विशेष यात्रा लाभ-एयरपोर्ट लाऊंडर, पिक-अप एवं ड्रॉप, मीटिंग एंड ग्रीट सेवा, वैश्वक गोल्फ प्रिविलेज, एड ग्रीट सेवा, वैश्वक गोल्फ प्रिविलेज, एकीकृत शोध ब्रांड और बहुत कुछ शामिल हैं।

परिष्कृत निवेश के अवसरों पर पर ध्यान केंद्रित करने वाले हर व्यक्तिगत समाधानों की तरफ, उच्चवृत्ति के प्रति हाप्तों को प्रदान की जाने वाली व्यूखला, पारपरिक से लेकर तात्त्वातीन, एस्टेट और एचएनडब्ल्यूआई ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप शानदार जीवनशैली का अनुभव प्रदान करता है। ये अभूतपूर्व लाभों और सुरक्षाओं के साथ आते हैं,

संक्षिप्त समाचार

हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए की बैठक संपन्न



रायपुर (विश्व परिवार)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त भाजपा प्रदेश कार्यालय रायपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांधीजी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री किण्णनंदेश, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, संगठन महामंत्री श्री पवन कुमार साय, सहित वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक में बैठने वाले श्री अंगेश वाथरी, श्री टंकराम श्री दयालदास बघेल, भाजपा प्रदेश महासचिव श्री संजय श्रीवास्तव विधायक आरंगे गुरु खुशबूत साहब सहित पार्टी पदाधिकारी अपेक्षित सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए नेताओं ने अपने विचार प्रकट किया तथा इस अभियान में पूरी ताकत के साथ जुड़ने का आवाहन किया।

कलिंगा विवि ने शासकीय चिकित्सालय - अरंग को हाइड्रोलिक डिलीवरी टेबल भेंट किया गया



अरंग। कलिंगा विश्वविद्यालय मध्य भारत का एक प्रतिष्ठित वैशिक्षणिक संस्थान है। जहाँ पर्यावरण के माध्यम से विकास के लिए अवधारणा समग्री का वितरण किया जाता रहा है। जनहित के इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हुए कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शासकीय चिकित्सालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक समग्री का वितरण किया जाता रहा है। इसी क्रम में कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय चिकित्सालय अरंग को हाइड्रोलिक डिलीवरी टेबल भेंट किया गया।

प्रसूति वार्ड में डिलीवरी टेबल एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो माँ और नवजात शिशु दोनों की सुरक्षा और आपात सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें प्रसव के दौरान माँ को पर्याप्त सहायता और आपात प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा सभी समय पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों को उनकी जरूरत के मुताबिक आवश्यक बुनियादी समग्री उपलब्ध करायी जाती है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शासकीय चिकित्सालय को सर्वविधायक बनाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को आधुनिकतम चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती रहे। इसी तात्पर्य में कलिंगा विश्वविद्यालय के कलानुसासक डॉ विजय अनंद और उनकी टीम द्वारा शासकीय चिकित्सालय - अरंग के छंड चिकित्सा अधिकारी डॉ विजयलक्ष्मी अनंत को हाइड्रोलिक डिलीवरी टेबल सौंपा गया, जिससे चिकित्सालय में चिकित्सकों को प्रसव और उसके विभिन्न चरणों को समायोजित करने में सुविधा रहेगी।

विद्युत उपक्रेन्द्र निर्माण में लापरवाही, 2 टेकेदार ब्लैकलिस्टेड, 33 को कड़ी चेतावनी

रायपुर (विश्व परिवार)

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष पी. दयानंद ने आज विद्युत अध्येतरंचना विकास के संबंधित कार्यों की समीक्षा की। जिसमें संस्थाओं द्वारा लंबे समय से कार्यों में लापरवाही की जा रही है और जिनके कारण निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं हो पा रहे हैं ऐसी 2 संस्थाओं को तीन वर्षों की लिए ब्लैकलिस्ट दिया गया। एक संस्था के निवेदन पर उसके कार्य पूर्ण करने के लिए 3 माह का समय दिया गया यदि इस समयावधि में उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया तो उन्हें भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा 32 संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री दयानंद ने क? तेवर दिखाए हुए चेतावनी दी कि विद्युत विकास कार्यों में कोताही बदाश नहीं की जाएगी।

श्री दयानंद ने आज छत्तीसगढ़ स्टेट ट्रांसमिशन ने एक विकास कार्यों के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसंहित कंवर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.), प्रधानमंत्री जननामित आदिवासी न्याय महाअभियान



(पी.एम. जननम) तथा मुख्यमंत्री विद्युत अध्येतरंचना विकास योजना की वितरण निर्धारित कार्यों को लंबे समयों में लापरवाही की जा रही है और जिनके कारण निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं हो पा रहे हैं ऐसी 2 संस्थाओं को तीन वर्षों की लिए ब्लैकलिस्ट दिया गया।

श्री दयानंद ने आज छत्तीसगढ़ स्टेट ट्रांसमिशन ने एक विकास कार्यों के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसंहित कंवर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.), प्रधानमंत्री जननामित आदिवासी न्याय महाअभियान

राज्यपाल रमेन डेका ने किया राजभवन का निरीक्षण

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन का निरीक्षण किया। उन्होंने सचिवालय की विभिन्न



शाखाओं का अवलोकन किया और जानकारी ली। श्री डेका ने राजभवन के दरवार हाँलेस सभाक्षण निवास कार्यालय सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया और हलवाई, संयुक्त सचिव तृष्ण सोनी, अविंद आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर उप सचिव सोनवानी सहित सभी कार्यकारियों सदस्यों ने गरबा दुख व्यक्त करते हुए श्रीमती हिना अनिषेष नेताओं एवं राजभवन के अन्य सभी सदस्यों ने गरबा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी प्रियंका कुमार जैन द्वारा मैं विश्व परिवार इंडस्ट्रीज, लॉन्ट नं.-421 सेक्टर-सी, मस्कुक नं.-7 उरला इंडस्ट्रीयल एरिया उरला, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ऑलप्रिय जिम के पीछे, सेक्टर-1, शक्ति नगर रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक : प्रदीप कुमार जैन, फोन नं. : 0771-4017966, मो. - 9981924252 RNI.NO.CHHIN/2013/50354

संचालनालय से मंत्रालय तक फेडरेशन ने मथाल ऐली निकालकर मंत्रालय के समक्ष किया जंगी प्रदर्शन



रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडेरेशन ने संचालनालय (इंद्रावती भवन) से मंत्रालय (महानदी भवन) तक मथाल चेतना रैली निकालकर राजनीति वालों की गारंटी लागू करने के बजाय मौत धराने के पर आक्रोश व्यक्त किया। रैली में प्रदेश के सभी संघों जिला/लॉक/प्रतिनिधियों ने मंत्रालय से सामने जान कर इनकार हमर सुनव सरकार अंदोलन के प्रथम चरण में जमर और प्रदर्शन किया।

उल्लेखनीय है कि फेडेरेशन ने मोदी की गारंटी का क्रियान्वयन नहीं होने के स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन का एलान किया है, जिसके अंतर्गत द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त 2024 तक संसदों एवं विधायिकों को जापान, तीव्री चरण में 24 सितंबर 24 को जिला/लॉक/तहसील में मथाल चेतना रैली विधायिक अधिकारी अपेक्षित सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए नेताओं ने अपने विचार प्रकट किया तथा इस अभियान में पूरी ताकत के साथ जुड़ने का आवाहन किया।

कलिंगा विवि ने शासकीय चिकित्सालय - अरंग को हाइड्रोलिक डिलीवरी टेबल भेंट किया गया



आरंग। कलिंगा विश्वविद्यालय मध्य भारत का एक प्रतिष्ठित वैशिक्षणिक संस्थान है। जहाँ पर्यावरण भागद के अनुरूप उच्च गुणवत्तापूर्ण और अनुसंधान केंद्रिय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अपनी स्थानांतरिक जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया जाता रहा है। जनहित के इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हुए कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शासकीय चिकित्सालयों के विकास के लिए आवश्यक समग्री का वितरण किया जाता रहा है। इसी क्रम में कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय चिकित्सालय अरंग को हाइड्रोलिक डिलीवरी टेबल भेंट किया गया।

प्रसूति वार्ड में डिलीवरी टेबल एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो माँ और नवजात शिशु दोनों की सुरक्षा और आपात सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें प्रसव के दौरान माँ मां को पर्याप्त सहायता और आपात प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा सभी समय पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों को उनकी जरूरत के आधारकारी आवश्यक समग्री का वितरण किया जाता रहा है। इसी क्रम में कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय चिकित्सालय अरंग को हाइड्रोलिक डिलीवरी टेबल भेंट किया गया।

गई श्री संजीव कुमार, मंडल रेल प्रबंधक, अध्यक्ष, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ, रायपुर मंडल रेलवे खेल विधायिक अधिकारी के विदर्शन के संयोग व्यक्त किया गया साथ ही खिलाड़ियों के द्वारा खेल के लिए दिये गये सुझावों के बारे में स्मारक ग्रन्थालय के द्वारा खेल संघ से प्रवेश किया गया। श्री संजीव कुमार ने दिया गया साथ ही खिलाड़ियों के द्वारा खेल के लिए दिये